व्हाइट शुगर पर लगेगा 20% आयात शुल्क

शशि कुमार झा/आर.एस. राणा

के. वी. थॉमस ने बताया

- रॉ-शुगर के आयात को शुल्क मुक्त करने का भी प्रस्ताव
- देश में मांग के मुकाबले ज्यादा है चीनी की कुल उपलब्धता
- इसलिए ओजीएल के तहत जारी रहेगा चीनी का निर्यात
- पीडीएस में चीनी की कीमत बढ़ाने का अभी कोई इरादा नहीं
- लेवी चीनी की मात्रा घटाने की अभी कोई योजना नहीं

खाद्य मंत्री से विशेष बातचीत पेज 9 पर

नई दिल्ली • व्हाइट चीनी पर आयात शुल्क को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा रॉ-शुगर के आयात को शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री प्रो. के. वी. थॉमस ने 'बिजनेस भास्कर' को विशेष बातचीत में बताया कि चालू पेराई सीजन के दौरान देश में चीनी का उत्पादन घटकर 230-235 लाख टन रह जाने का अनुमान है जो पिछले साल के 262 लाख टन से कम है। वहीं, चालू पेराई सीजन के शुरू में 60 लाख टन चीनी का बकाया स्टॉक बचा हुआ था जबकि देश में चीनी की सालाना खपत 220 लाख टन की होती है। अतः चीनी की कुल उपलब्धता मांग के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत चीनी का निर्यात जारी रहेगा।

वर्तमान में व्हाइट और रॉ-शुगर के आयात पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगता है। थॉमस ने कहा कि व्हाइट चीनी के आयात पर शुल्क को 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव है, जबकि रॉ-शुगर के आयात को शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव है। इस बारे में फैसला कैबिनेट कमेटी को करना है। पीडीएस में चीनी की कीमत बढ़ाने और लेवी चीनी की मात्रा घटाने की अभी कोई योजना नहीं है जो फिलहाल 10 फीसदी है।

चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। थॉमस कहते हैं कि इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाने की पूरी तैयारी है। उम्मीद है कि वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को पूर्ण स्वायत्तता देने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेग्युलेशन एक्ट (एफसीआरए) को भी संसद में मंजूरी मिल जाएगी, जिससे जिंस बाजार में कारोबार करने वाले छोटे निवेशकों के साथ-साथ किसानों को भी फायदा होगा।

केंद्रीय पूल में गेहूं का बंपर स्टॉक होने के बावजूद गेहूं उत्पादों खासकर आटा की कीमतों में तेजी आने की वजह बताते हुए थॉमस ने कहा कि गेहूं के एमएसपी में पिछले दो-तीन सालों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा गेहूं की खरीद में मंडी टैक्स और अन्य कई खर्च जुड़ जाते हैं जिस वजह से गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 'ओएमएसएस' में 70 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन नवंबर 2012 से मार्च 2013 तक करने की योजना है।